



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2672]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2018/आषाढ़ 22, 1940

No. 2672]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2018/ASHADHA 22, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2018

का.आ. 3443(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि वित्त मंत्रालय के निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों, अर्थात् :-

- (क) भारत सरकार टकसाल, कोलकाता, नोएडा, मुम्बई और हैदराबाद (मद संख्या 11 में सम्मिलित);
- (ख) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक (मद संख्या 12 में सम्मिलित);
- (ग) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रैस, हैदराबाद (मद संख्या 12 में सम्मिलित);
- (घ) सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद (मद संख्या 21 में सम्मिलित);
- (ङ) बैंक नोट प्रैस, देवास (मद संख्या 22 में सम्मिलित);
- (च) करैसी नोट प्रैस, नासिक रोड (मद संख्या 25 में सम्मिलित),

जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 11, 12 [(ख) और (ग) दोनो] 21, 22 और 25 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जैसा ऊपर विनिर्दिष्ट है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया जाना चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार ने अंतिम बार उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 226 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2018 द्वारा तारीख 15 जनवरी, 2018 से छह मास कि अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में उक्त औद्योगिक उपक्रमों की लोक उपयोगी सेवा प्राप्ति को छह मास की और अवधि के लिए विस्तारित करना अपेक्षित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उप-खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उपक्रमों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 15 जुलाई, 2018 से छह मास की और अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/4/2011-आईआर (पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2018

S.O. 3443(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the following industrial undertakings in the Ministry of Finance, namely the—

- (a) India Government Mints, Kolkata, Noida, Mumbai and Hyderabad (covered under item No.11);
- (b) India Security Press, Nashik (covered under item No. 12);
- (c) Security Printing Press, Hyderabad (covered under item No. 12);
- (d) Security Paper Mill, Hoshangabad (covered under item No. 21);
- (e) Services in the Bank Note Press, Dewas (covered under item No. 22);
- (f) Currency Note Press, Nashik Road (covered under item No. 25),

which are covered under items 11, 12 [both (b) and (c)], 21, 22 and 25 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) as specified above, to be public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industrial undertakings to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 15th January, 2018 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 226(E), dated the 15th January, 2018;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industrial undertakings for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industrial undertakings to be public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 15th July, 2018.

[F. No. S.11017/ 4 /2011- IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.